भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 434
बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

देश में हीट वेव की चिंताजनक दर

†434. श्री अमर शरदराव काले:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री बरजंग मनोहर सोनवणे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड:
श्री संजय दीना पाटिल:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल के वर्षों में हीट वेव की चिंताजनक दर की ओर गया है और यदि हां, तो आगामी वर्षों में हीट वेव के कारणों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या पिछले जलवायु वर्ष में हीट वेव ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा आगामी वर्ष में हीट वेव के कारण होने वाले जीवन और आर्थिक क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रह हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य ने केंद्र सरकार को हीट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार हीट वेव से लड़ने संबंधी तैयारी को कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और संबद्ध हितधारको से किस प्रकार सहयोग करती है, ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा हीट वेव के प्रभाव को कम करने के लिए आवंटित किए गए वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में हीट वेव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बढाने और तैयारियों में सुधार करने के लिए मौसम विभाग और जलवायु विशेषज्ञों के साथ समन्वय करती है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हां। जलवायु परिवर्तन के कारण, वैश्विक स्तर पर वार्षिक तापमान बढ़ रहा है और इसका प्रभाव भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लू की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के रूप में दिख रहा है। इंटरगर्वनमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC)-छठवीं मूल्यांकन रिपोर्ट भी ठीक यही बात परिलक्षित करती है (https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf). भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के विश्लेषण के अनुसार सामान्य तौर पर, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों समेत मध्य भारत को कवर करने वाले हीट कोर जोन में लू की आवृत्ति की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने लू से संबंधित एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है, जिसमें भारत में लू से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान की गई है (https://mausam.imd.gov.in/responsive/met2.php)।

आगामी वर्षों में लू के कारणों को कम करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर विभिन्न पहल की हैं। इस दिशा में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) तथा स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (SAPCC) प्रमुख पहलों में से एक है। इसके अतिरिक्त, भारत ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस तथा कोएलिशन फॉर डिजास्टर-रिसाइलियेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभायी है। भारत विकास के लिए न्यूनतम-कार्बन कार्यनीतियों पर काम करने के लिए संकल्पबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से इस दिशा में काम कर रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) देश के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के साथ समन्वयन में निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है, जिससे लू समेत प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के दौरान जान-माल की हानि को कम करने में सहायता मिली है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के साथ सहयोग में लू की स्थितियों की अधिक संभावना वाले 23 राज्यों में संयुक्त रूप से हीट एक्शन प्लान (HAPs) कार्यान्वित किए गए ।

(ख) लू ने पिछले वर्ष फसल उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कुछ विशेष सब्जियों को, जिसके चलते खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ा। सरकार ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए समय रहते उपाय किए। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ये उपाय शामिल हैं - जरूरी खाद्य पदार्थों के बफर स्टॉक को सुदृढ़ बनाया जाना तथा आवधिक रूप से खुले बाजार में रिलीज किया जाना, निर्दिष्ट दुकानों में चावल, आटा तथा दाल जैसी वस्तुओं की बाजार से कम (सब्सिडाइज्ड) दरों पर बिक्री करना, शुल्क (ड्यूटीज) को युक्तिसंगत करके जरूरी खाद्य पदार्थों के आयात को सरल बनाना, स्टॉक लिमिट लगाने/उसमें संशोधन करने तथा निगरानी करने के माध्यम से जमाखोरी की रोकथाम करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुख्य रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि से सुरक्षा प्रदान करती है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य उन 23 राज्यों में से एक है, जहां हीट एक्शन प्लान (HAPs) पहले ही कार्यान्वित किया गया है।

(घ) लू पूर्वानुमान तथा चेतावनी सूचना सभी हितधारकों समेत संघ सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, तथा स्थानीय सरकारी निकायों को प्रदान की जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) आम जनता एवं आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण / पूर्वानुमान / चेतावनियां जारी करता है, ताकि वे चरम मौसमी घटनाओं समेत लू से बचाव के लिए तैयारी कर सकें। अलर्ट जारी करते समय, किसी संभावित प्रतिकूल मौसम के प्रभाव पर प्रकाश डालने तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आसन्न आपदा मौसम घटना के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में संकेत देने के लिए उपयुक्त कलर कोड का उपयोग किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पहले से तैयारी करने के लिए पहले से जरूरी चेतावनी एवं परामर्शिकाएं जारी करता है। ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने से काफी पहले ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की लू तैयारी संबंधी विभिन्न बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा ऋतु के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित होती हैं।

(ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) देशभर में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को एकसमान रूप से कार्यान्वित करता है, तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जलवायु एवं मौसम संबंधित पूर्वानुमान तथा चेतावनियों समेत लू संबंधी चेतावनियां प्रदान करता है।

(च) जी हाँ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पूर्व चेतावनी सेवाओं में सुधार करने के लिए समन्वित तरीके से अनुसंधान केंद्रों के साथ सहयोग करता है। यह विभाग अपनी उत्पाद पहुंच को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों तथा विशेषज्ञों समेत राष्ट्रीय, राज्य स्तर के आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों तथा स्थानीय सरकारी विभागों के साथ मिलजुल कर काम करता है।

लू से संबंधित तैयारी बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से अन्य सरकारी एजेंसियों एवं जलवायु विशेषज्ञों के साथ नियमित परामर्श एवं समन्वय बनाए रखा जाता है। ऋतुनिष्ठ तथा मासिक पूर्वानुमान, विभिन्न हितधारकों को तैयारी का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है, तथा विस्तारित अवधि पूर्वानुमान और उसके पश्चात लघु से मध्यम अवधि पूर्वानुमान में जमीनी कार्यवाही का अनुमान लगाया जाता है।

****